भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 198

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

पीएमआईएस के तहत युवाओं को इंटर्नशिप

198. श्री इटेला राजेंदर:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना की प्रायोगिक योजना के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों की तुलना में कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इसका उद्देश्य 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है;
(ख) विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक व्यावसायिक वातावरण का लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) उन प्रशिक्षुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और उन विभागों या मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रत्येक प्रशिक्षु को 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया है; और
(घ) यदि हां, तो विशेषकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): जी नहीं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों की तुलना में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक थी।

बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का लक्ष्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

3 अक्टूबर, 2024 से शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में, भागीदार कंपनियों द्वारा देश भर में 1.27 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए। इसके लिए लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए। पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में, भागीदार कंपनियों ने 60,866 उम्मीदवारों को 82,077 इंटर्नशिप ऑफर किए, जिनमें से 28,141 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए ऑफर स्वीकार कर लिए हैं। प्रदान किए गए इंटर्नशिप अवसरों और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त इंटर्नशिप प्रस्तावों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक ।में दिया गया है।

इस योजना के तहत, इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्न के शामिल होने पर सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्न को ₹6,000 का आकस्मिक अनुदान वितरित किया जाएगा, जो कंपनी द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए इंटर्न को 5,000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाना है। हर महीने, कंपनी इंटर्न की उपस्थिति और अच्छे आचरण के बारे में संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर अपने सीएसआर फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये जारी करती है। एक बार जब कंपनी भुगतान कर देती है, तो सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से इंटर्न को प्रति माह 4,500 रुपये जारी करेगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की जा रही है।

प्रथम चरण में 28,141 अभ्यर्थियों के स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष आकस्मिक व्यय हेतु कुल एकमुश्त अनुदान 4.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है तथा अब तक शामिल हुए प्रशिक्षुओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान कर दिया गया है। राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II पर दिया गया है। एक महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं को अब तक लगभग 1.3 करोड़ रुपये की मासिक सहायता स्वीकृत की गई है।

पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट का दूसरा दौर 9 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है, और कंपनियां नए इंटर्नशिप अवसरों को पोस्ट करने के साथ-साथ खाली पड़े इंटर्नशिप अवसरों को भी संपादित करने की प्रक्रिया में हैं।

*****

अनुलग्नक-I

03 फरवरी, 2025 उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 का अनुलग्नक

पीएम इंटर्नशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट (राउंड-I) में दिए गए इंटर्नशिप के अवसरों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	इंटर्नशिप के अवसरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12
2	आंध्र प्रदेश	4973
3	अरुणाचल प्रदेश	156
4	असम	3457
5	बिहार	2802
6	चंडीगढ़	523
7	छत्तीसगढ़	3334
8	दिल्ली	2470
9	गोवा	1017
10	गुजरात	11690
11	हरियाणा	7764
12	हिमाचल प्रदेश	1254
13	जम्मू और कश्मीर	761
14	झारखंड	3535
15	कर्नाटक	10022
16	केरल	2807
17	लद्दाख	72
18	लक्षद्वीप	2
19	मध्य प्रदेश	5627
20	महाराष्ट्र	13664
21	मणिपुर	73
22	मेघालय	55
23	मिजोरम	25
24	नागालैंड	45
25	ओडिशा	5142
26	पुडुचेरी	310
27	पंजाब	2314
28	राजस्थान	4653
29	सिक्किम	254
30	तमिलनाडु	14585
31	तेलंगाना	7913
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	232
33	त्रिपुरा	395
34	उत्तर प्रदेश	9027
35	उत्तराखंड	1966
36	पश्चिम बंगाल	4577
	कुल योग	**127508**

पीएम इंटर्नशिप योजना के पहले दौर में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या- पायलट परियोजना

क्र.सं.	आवेदकों की स्थिति	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20
2	आंध्र प्रदेश	6164
3	अरुणाचल प्रदेश	29
4	असम	3843
5	बिहार	5668
6	चंडीगढ़	117
7	छत्तीसगढ़	2284
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	40
9	दिल्ली	2698
10	गोवा	28
11	गुजरात	4541
12	हरियाणा	5990
13	हिमाचल प्रदेश	929
14	जम्मू और कश्मीर	769
15	झारखंड	2699
16	कर्नाटक	3098
17	केरल	1938
18	लद्दाख	34
19	मध्य प्रदेश	6244
20	महाराष्ट्र	3718
21	मणिपुर	71
22	मेघालय	45
23	मिजोरम	5
24	नागालैंड	58
25	ओडिशा	3267
26	पुडुचेरी	105
27	पंजाब	742
28	राजस्थान	4314
29	सिक्किम	15
30	तमिलनाडु	2347
31	तेलंगाना	4439
32	त्रिपुरा	200
33	उत्तर प्रदेश	11563
34	उत्तराखंड	622
35	पश्चिम बंगाल	3433
	कुल योग	**82,077**

अनुलग्नक-II

03 फरवरी, 2025 उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 का अनुलग्नक

इंटर्न को भुगतान किए गए 6000 रुपये के एकमुश्त अनुदान की राज्यवार राशि

क्र.सं.	**राज्य**	**एकमुश्त अनुदान की राशि 6000 रु. का भुगतान**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24000
2	आंध्र प्रदेश	1992000
3	अरुणाचल प्रदेश	42000
4	असम	5574000
5	बिहार	3708000
6	चंडीगढ़	84000
7	छत्तीसगढ़	1110000
8	दिल्ली	1860000
9	गोवा	12000
10	गुजरात	1182000
11	हरियाणा	1380000
12	हिमाचल प्रदेश	330000
13	जम्मू और कश्मीर	534000
14	झारखंड	1902000
15	कर्नाटक	1398000
16	केरल	1188000
17	लद्दाख	54000
18	मध्य प्रदेश	3264000
19	महाराष्ट्र	1866000
20	मणिपुर	138000
21	मेघालय	54000
22	मिजोरम	6000
23	नागालैंड	30000
24	ओडिशा	2478000
25	पुडुचेरी	48000
26	पंजाब	294000
27	राजस्थान	1794000
28	सिक्किम	6000
29	तमिलनाडु	864000
30	तेलंगाना	1452000
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12000
32	त्रिपुरा	186000
33	उत्तर प्रदेश	6294000
34	उत्तराखंड	390000
35	पश्चिम बंगाल	2274000
	कुल योग	**43824000**